

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2003/आश्विन 8, 1925

No. 238 ]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2003/ASVINA 8, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2003

सं. 26 (आरई-03)/2002—07

फा. सं. 01/94/180/18/एम 04/पी.सी.-IV/978.—निर्यात और आयात नीति, 2002—07

के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 5.3, 5.3.1 और 5.3.2 की तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाता है जहाँ क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा ई पी सी जी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया तथा मुख्यालय में ई पी सी जी समिति द्वारा अन्तर्संबंध के अन्तिम निर्धारण का उल्लेख किया गया है। उक्त पैराग्राफ को निम्नवत संशोधित किया गया है :—

5.3 आवेदक स्वघोषणा के आधार पर क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अन्तर्संबंधों के अन्तिम निर्धारण के मद्दे पर ई पी सी जी लाइसेंस के लिए क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है जहाँ बचाए गए शुल्क की रकम 50 करोड़ रु० तक है। आवेदक को इस आशय की वचनबद्धता भी देनी होगी कि यदि क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जिग्स, फिक्चर्स, डाइस, माउल्ड्स और स्पेयर्स समेत पूंजीगत माल की अनुमति न देने की स्थिति में लाइसेंसधारक इन वस्तुओं पर यथा लागू सीमाशुल्क के साथ-साथ 15% ब्याज भी अदा करेगा।

उन मामलों में जहाँ बचाए गए शुल्क की रकम 50 करोड़ रुपये से ज्यादा है, आवेदक संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजते हुए एक प्रति विदेश व्यापार महानिदेशालय मुख्यालय को सीधे आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में, मुख्यालय की ई पी सी जी समिति जो इन मामलों में अर्न्तसंबंधों का भी निर्धारण करेगी, की सिफारिशों के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी तदनुसार ई पी सी जी लाइसेंस जारी करेगा।

5.3.1 ई पी सी जी लाइसेंस, जिसमें बचाए गए शुल्क की रकम 50 करोड़ रुपये तक है, के जारी होने के बाद, क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय प्रमुख के नेतृत्व में अधिकारियों की एक समिति तथा मुख्यालय में ई पी सी जी समिति जहाँ बचाए गए शुल्क की रकम 50 करोड़ रुपये से ज्यादा है, चार्टर्ड इंजिनियर के प्रमाण पत्र और उनके द्वारा कायम ई पी सी जी अर्न्तसंबंध मानदण्ड के आधार पर, निर्धारित 2 महीने की अवधि के भीतर अर्न्तसंबंधों को अन्तिम रूप देगी। अर्न्तसंबंध को अन्तिम रूप देते समय मौजूदा निर्यात आयात नीति/प्रक्रिया में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा। क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों की समिति, लाइसेंस जारी होने के दो महीने के भीतर यदि अर्न्तसंबंध को अन्तिम रूप देने में असफल रहती है तो यथा आवेदित अर्न्तसंबंध को अन्तिम माना जाएगा। तथापि, जहाँ दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत न किए जाने के कारण अर्न्तसंबंधों के निर्धारण के लिए आवेदन को रद्द किया जाता है, वहाँ लाइसेंस धारक को यथा लागू सीमा शुल्क के साथ-साथ 15% ब्याज भी अदा करना होगा।

5.3.2 प्रत्येक क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी क्षेत्रवार/उद्योगवार एक अलग रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक निर्यात उत्पाद/सेवा के मद्दे पूंजीगत माल को दर्शाना होगा तथा जो किसी मामले में मुख्यालय द्वारा पहले से सूचित अर्न्तसंबंध के आधार पर तथा समय-समय पर स्वयं क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नियमित अर्न्तसंबंध मामलों के आधार पर जिनका अर्न्तसंबंध मामलों के जाँच के दौरान उल्लेख किया जाता है तथा उन्हें नियमित किया जाता है, के आधार पर होगा।

2. प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित परिशिष्ट 9 के “आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों” की सूची में क्रम सं० 5 के बाद निम्नलिखित दस्तावेज जोड़े गए हैं:-

“6. चार्टर्ड इंजिनियर का प्रमाण पत्र जो प्रमाणित करता है :-

- (i) निर्यात दायित्व हेतु उत्पाद के विनिर्माण के लिए ई पी सी जी स्कीम के तहत आयात हेतु मशीनरी का अन्तिम प्रयोग (मशीनरी के अन्तिम प्रयोग को विस्तार से स्पष्ट करें)

और/अथवा

- (ii) आयात हेतु प्रस्तावित हिस्से पुर्जों की आवश्यकता तथा मौजूदा मशीनरी निर्यात करने/आयात के लिए माँगी गई मशीनरी का विनिर्माण करने के लिए मौजूदा मशीनरी हेतु मात्रा की आवश्यकता

और/अथवा

- (iii) भारत में किसी अन्य देश के विदेशी ग्राहकों/सेवा ग्राहकों के लिए सेवा की आपूर्ति हेतु ई पी सी जी स्कीम के तहत आयात के लिए माँगे गए उपकरणों/वस्तुओं का पूर्ण इस्तेमाल करना ताकि निर्यात से संबंधित विदेशी मुद्रा का अर्जन करना/मुक्त विदेशी मुद्रा में भारत में सेवाओं की आपूर्ति करना।

7. भेषज उत्पाद के निर्यात के मामले में औषधि विनिर्माण लाइसेंस की एक प्रति अथवा अन्य उत्पादों के मामले में आई ई एम/एस एस आई पंजीकरण नम्बर की एक प्रति प्रस्तुत करना।”

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एल. मानसिंह, महानिदेशक, विदेश व्यापार

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 30th September, 2003

No. 26 (RE-03)/2002—07

**F. No. 01/94/180/18/AM 04/PC-IV/978.**—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Export and Import Policy, 2002—07, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the Handbook of Procedures (Vol. 1):—

1. Attention is invited to Paragraph 5.3, 5.3.1 and 5.3.2 of the Handbook of Procedure whereby the procedure for issuance of EPCG License by the RLA office and the final fixation of nexus by EPCG Committee at Headquarters has been mentioned. The said paragraphs stand amended as follows :-

5.3 The applicant may apply for EPCG license wherein duty saved amount is upto Rs. 50 crores to the Regional Licensing Authority (RLA) on the basis of self-declaration subject to final fixation of nexus by the RLA. The applicant shall give an undertaking that in case the RLA subsequently disallows the Capital Goods including jigs, fixtures, dies, moulds and spares, the license holder shall pay customs duty as applicable together with 15% interest on such goods.

For the cases wherein duty saved amount is above Rs. 50 crores, the applicant may apply to DGFT headquarters directly with a copy endorsed to the concerned RLA. In such cases, based on the recommendations of Headquarters EPCG Committee which will also fix the nexus in these cases, the concerned RLAs will issue the EPCG License accordingly.

5.3.1 After issuance of an EPCG License wherein duty saved amount is upto Rs. 50 crores, a Committee of officers of the RLA, headed by the Head of Office, and the EPCG Committee in the Headquarters where duty saved amount is more than Rs. 50 Crores, shall finalize the nexus within the stipulated period of two months on the basis of the Chartered Engineer's certificate and on the basis of EPCG nexus norms maintained by them. While finalizing the nexus, the provisions contained in the existing Export Import Policy/Procedures will be taken into account. In case, the Committee of officers at RLA fails to finalize the nexus within two months from the date of issuance of license, the nexus as applied for shall be treated as final. However, where the application for fixation of nexus is rejected on account of non-furnishing of documents/information, the license holder shall be liable to pay customs duty as applicable together with 15% interest thereon.

5.3.2 Each RLA shall maintain a separate register sector-wise/industry-wise showing the CGs allowed against each export product/service on the basis of nexus already communicated by HQ in a case and on the basis of nexus cases regularized by the RLA themselves from time to time which should be referred to while examining the nexus cases and to regularize them.

2. In the list of "Documents to be enclosed with the application form" of Appendix 9 given in Handbook of Procedure, following documents after Sl. No. 5 is added :-

"6. A Chartered Engineer Certificate certifying :-

- (i) End use of machinery sought for import under EPCG Scheme for manufacture of the product undertaken for Export Obligation (explaining the end use of machinery in detail);

and/or

- (ii) The essentiality of spare parts sought for import and its required quantity for existing machinery manufacturing the goods to be exported/ machinery sought for import;

and/or

- (iii) Complete usage of equipments/goods sought for import under the EPCG Scheme for supply of service to overseas customers/ service

consumers of any other country in India to earn free foreign exchange/supply of service in India relating to export paid in free foreign exchange.

7. Copy of Drug Manufacturing License in case of export of Pharmaceutical product or copy of IEM/SSI Registration Number in case of other products.”

This issues in public interest.

L. MANSINGH, Director General of Foreign Trade

2832 41/03